which appeared in the Indian Express of the 12th September, 1992;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) what remedial steps Government have taken or propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) The French Consortium executing the Dulhasti Hydro-electric Project on turn-key basis had suspended work on the project since August 24, 1992 following some law and order disturbances in and around the project area, demanding a categorical assurance from the National Hydro-electric Power Corporation (NHPC), about safety and security of their personnel and property. They had recently resumed work with the repairs to the Tunnel Boring Machine (TBM) which had been damaged sometime back due to heavy ingress of water in the tunnel.

(c) A high level team consisting of senior officials of the State Government and security agencies had visited the project site on 30-8-1992 followed by a visit by the Governor of J&K on 31-8-1992 and discussions were held with the French Contractor and NHPC authorities. An assurance of security had been extended to them and security arrangements were augmented to take care of patrolling the 33 km. stretch between Dul and Hasti and the residential colony of the French personnel and the protect area.

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1330. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अपने कतिपय विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होने के बारे में गंभीर संदेह है ;

(ख) क्या इस संबंध में विश्व बैंक ने कोई नीति बनाई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भारत को स्वीकार्य और अस्वीकार्य शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री प्रेस्टन के भारत आगमन पर उनसे इस मामले पर बातचीत की है, यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) विश्व बैंक से ऋण न मिलने के कारण कौन-कौन से विद्युत संयंत्र/परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगे; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वैकल्पिक योजना बनाई है, यदि हां , तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) "समयमान" (टाइम स्केल) धारणा के अधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं का वित्त पोषण किए जाने समेत विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने, राज्य बिजली बोर्डों की ओर केन्द्रीय विद्युत निगमों की बकाया राशियों को कम करने और राज्य बिजली बोर्डों को हो रहे घाटे समेत कुछ जारी की गई नीतियों के बारे में बैंक ने सरकार से पुष्टि की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने भारत के दौरे के दौरान विद्युत मंत्री से मुलाकात की थी । विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की सरकार की इच्छा से मंत्री महोदय ने अवगत करा दिया है।

(घ) और (ङ) अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ पावर ग्रिड निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं का वित्त पोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है । मूल्यांकन कार्य अलग से भी किया जा रहा है।